# Rajasthan Service Rules

# FOREIGN SERVICE


**Dr. R.K.Choubisa**

**Professor of Public Administration**

**HCM Rajasthan State Institute of Public Administration**

**JAIPUR-302 017 [Rajasthan] INDIA**

**Telephone No. 0141-2715211 Fax 0141-2705420**

**09414168624**

**www.hcmripa.gov.in**

**e-mail: rkchoubisaripa@hotmail.com**

# REFERENCE:

**Rajasthan Service Rules, 1951, Vol. I Part III, Chapter VII**

**Rule 51 Deputation out of India**

**Rajasthan Service Rules, 1951, Vol. I Part V, Chapter XIII**

**Rule 141-157 Foreign Service**

# Government Accounts

1. Consolidated Fund
2. Contingency Fund
3. Public Account

## *Consolidated Fund:*

- ***Established under Article 266 of the Constitution of India***
  - **All transactions of all revenues received by the Government of Rajasthan;**
  - **All loans raised by the Government by issue of treasury bills.**
  - **Loans or ways and means advances .**
  - **All moneys received by the Government in repayment of loans.**

# राज्य की संचित निधि

- राज्य सरकार की सम्पूर्ण आय, ऋण प्राप्ति तथा उसके द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी से प्राप्त आय को मिलाकर राज्य का संचित कोष बनता है।
- सरकार के सारे खर्च इसी कोष से पूरे होते है परन्तु इस कोष से धन की निकासी विधानसभा की अनुमति से ही सम्भव है।

# Consolidated Fund

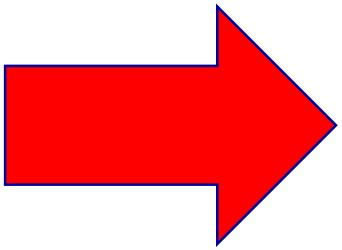

Board
Company
Corporation
Autonomous Body
Society
Foreign Service

# RULE 51: Deputation out of India

- Temporarily deputed for duty out of India
- Either in connection with the post held by him/her in India or
- In connection with any special duty on which he/she may be temporarily placed.
- His/her pay and allowances shall be regulated ordinarily in accordance with the rules applicable to officers of the Government of India. (F.R. 51(1)

# RULE 51: Training Abroad

- The Colombo Plan
- The Point Four Programme
- Rock Feller Foundation
- Ford Foundation
- UNDP
- World Bank
- USAID
- Exchange Programmes.

# RULE 141: Employees consent necessary for transfer to foreign service

- No Government Servant may be transferred to foreign service against his will.
- Government may transfer a Government Servant to a body incorporated which is wholly or substantially owned or controlled by the Government.

# RULE 142: When transfer to foreign service admissible.

A transfer to foreign service is not admissible unless:

- The duties to be performed after the transfer are for public reasons
- The Government Servant transferred holds a post paid from the consolidated fund or holds a lien on such a post had his lien not been suspended.

# RULE 143: Consequences of transfer to foreign service during leave.

- If a Government Servant is transferred to foreign service while on leave he ceases, from the date of such transfer, to be on leave and to draw leave salary.
- He remains in the cadre or cadres in which he was working.
- He may be given such substantive or officiating promotion in those cadres.

# RULE 144: Date from which Government Servant in foreign service draws pay from foreign employer:

- From the date on which he relinquishes charge of his post in Government Service.

# RULE 144-A: Conditions of deputation on foreign service.

- A Government Servant may be transferred on deputation/foreign service to:
  - Central Government;
  - Other State Government;
  - Public Sector Undertakings;
  - Autonomous Bodies (Whether incorporated or not);
  - Other bodies wholly/or substantially controlled by the Government etc.

# DEPUTATION

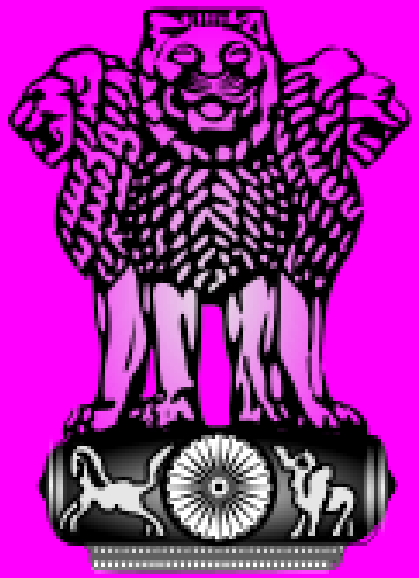

सत्यमेव जयते

- Central Government;
- Other State Government;
- Public Sector Undertakings;
- Autonomous Bodies (Whether incorporated or not);
- Other bodies wholly/or substantially controlled by the Government etc.

# REVERSE DEPUTATION

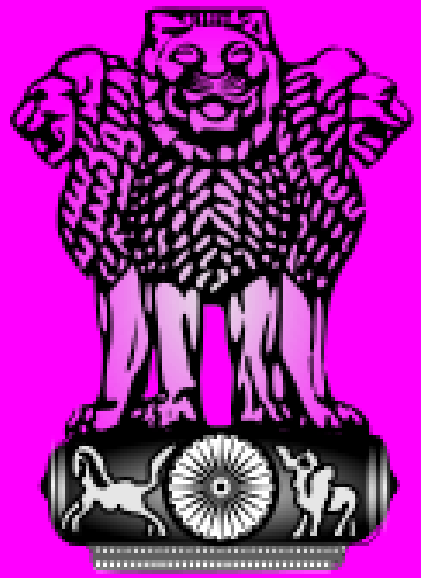


- Central Government;
- Other State Government;
- Public Sector Undertakings;
- Autonomous Bodies (Whether incorporated or not);
- Other bodies wholly/or substantially controlled by the Government etc.

# DEPUTATION

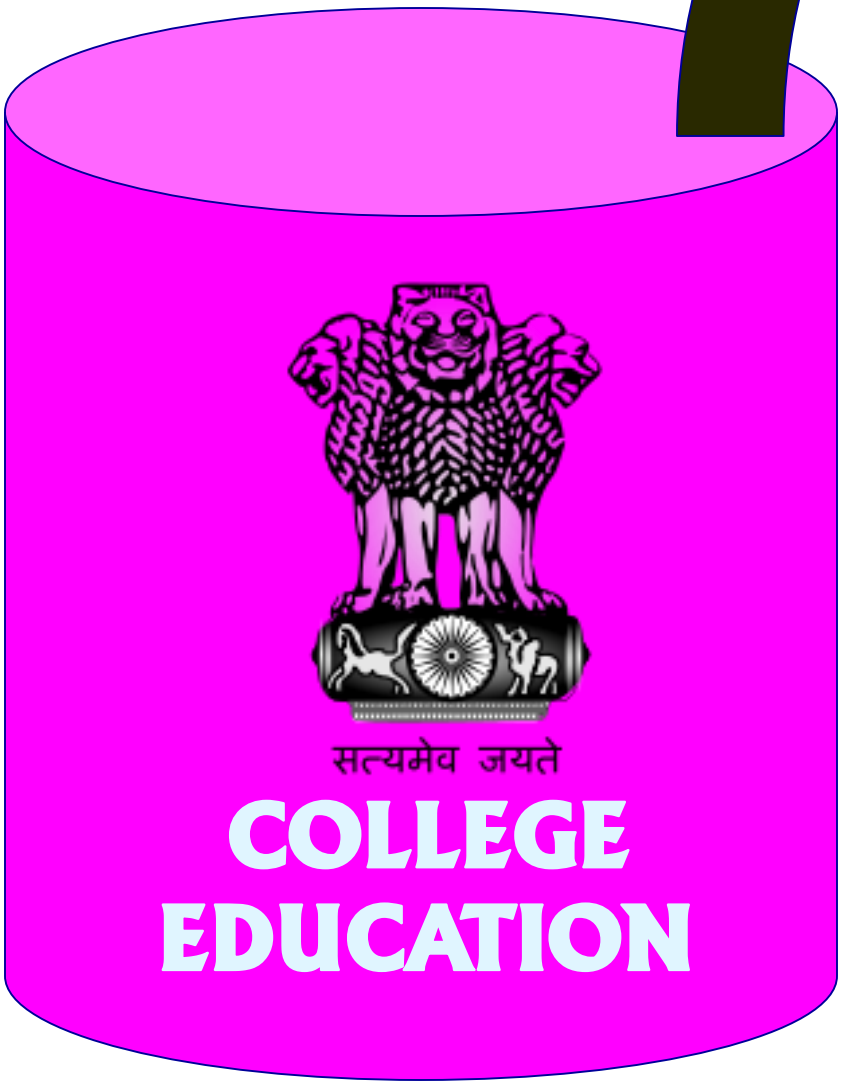

# LENDING AUTHORITY

COLLEGE EDUCATION

# BORROWING AUTHORITY

HCM RIPA

# प्रतिनियुक्ति

- एक राज्य कर्मचारी वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर अधिकतम 4 वर्ष रह सकेगा।
- प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जा सकता है।
- राज्य हित में यदि प्रतिनियुक्ति अवधि बढाना नितान्त आवश्यक हो तो संबंधित प्रशासनिक विभाग ऐसी अवधि को 1 वर्ष और बढाने को प्राधिकृत माने जायेगें। 4 वर्ष बाद प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
- 5 वर्ष प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि है।

वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.1(47)वि.वि(ग्रुप–2)/82
दिनांक 22 जनवरी 1986 दिनांक 1 फरवरी 1986 से प्रभावी

# विपरीत प्रतिनियुक्ति

- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/2003 पार्ट–I दिनांक 17 फरवरी 2007
- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक प.1(3)वित्त/नियम/2005 पार्ट–I दिनांक 17 मई 2011
- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/2003 पार्ट–I दिनांक 16 जनवरी 2015
- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक प.1(4)वित्त/नियम/2015 दिनांक 16 नवम्बर 2017

# विपरीत प्रतिनियुक्ति

- प्रशासनिक विभाग कार्मिक के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव औचित्य सहित वित्त विभाग को भिजवाये जायेंगे।
- प्रस्ताव में कार्मिक की शैक्षणिक योग्यता, कार्मिक द्वारा सम्पादित कार्यो का विवरण भेजा जायेगा। विभाग कार्मिक की प्रतिनियुक्ति के लिये उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगा।

वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक प.1(4)वित्त/नियम/2015
दिनांक 16 नवम्बर 2017

# विपरीत प्रतिनियुक्ति

- उपयुक्त पाये गये कार्मिक का
  - गत 7 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों (PAR) में से 5 बहुत अच्छे होने चाहिये,
  - कार्मिक के विरूद्ध विभागीय जाँच/न्यायिक प्रकरण बकाया न हो, और
  - अनुशासनिक नियमों के तहत दण्डनीय कार्यवाही न हो।

वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक प.1(4)वित्त/नियम/2015
दिनांक 16 नवम्बर 2017

# विपरीत प्रतिनियुक्ति

- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर समकक्ष कर्मचारी को लिये जाने से पूर्व
  - गत 7 वर्षों में नियमित वेतन वृद्धि प्राप्त हो,
  - अनुशासनिक नियमों के तहत कार्यवाही न हो
  - विभागीय जाँच/न्यायिक प्रकरण बकाया न हो
  - उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर वित्त विभाग को भिजवाना होगा।

# विपरीत प्रतिनियुक्ति

- प्रथमतः प्रतिनियुक्ति वित्त विभाग की सहमति से एक वर्ष के लिये होगी।
- प्रशासनिक विभाग के स्तर से लोक हित में प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी।
- प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः किसी भी परिस्थिति में 5 वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।

# विपरीत प्रतिनियुक्ति

- 5 वर्ष की विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर संबंधित कार्मिक को पैतृक संस्थान के लिये कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5 वर्ष की विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर अवधि में और अभिवृद्धि के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगें।
- फिर भी यदि किन्हीं विशिष्ट कारणों से अवधि बढाया जाना आवश्यक हो तो प्रशासनिक विभाग प्रकरण वित्त विभाग को भिजवायेगें।

वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक प.1(4)वित्त/नियम/2015
दिनांक 16 नवम्बर 2017

# विपरीत प्रतिनियुक्ति

- ऐसे प्रस्तावों पर अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव वित्त के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।
- प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति के कम से कम 2 माह पूर्व औचित्य सहित प्रस्ताव कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग को भिजवाये जायेंगे।
- प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की शर्तों का प्रतिनियुक्ति से पूर्व वित्त विभाग से अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य है।

# विपरीत प्रतिनियुक्ति

- प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली कटौतियों को संबंधित सरकार/उपक्रम को समय समय पर भिजवाये जाने का उत्तरदायित्व सेवा उधार लेने वाले राजकीय विभाग के संबंधित अधिकारी का होगा।

वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक प.1(3)वित्त/नियम/2005 पार्ट–1
दिनांक 17–5–2011

# RULE 145: Contributions towards Leave and Pension

- Contribution towards the cost of his pension must be paid to the Consolidated Fund on his behalf.
- Contribution must be paid on account of the cost of leave salary also.
- Rate of pension and leave salary will be prescribed by the Government.

Thanks